In Chapter Two we read about the emergence of the Congress system. This system was first challenged during the 1960s. As political competition became more intense, the Congress found it difficult to retain its dominance. It faced challenges from the opposition that was more powerful and less divided than before. The Congress also faced challenges from within, as party could longer no accommodate kinds all of differences. In this chapter we pick the story from where we left it in Chapter Two, in order to

इस किताब के दूसरे अध्याय में आपने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में पढ़ा था। इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी और एसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थीं। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज्यादा ताकतवर था। कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झलनी पड़ीं, क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर की विभिन्नता को एक साथ थामकर नहीं चल पा रही थी। इस अध्याय में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे, जहां पर दूसरे अध्याय में छोड़ी गइं थी, ताकि हम समझ सकें कि

- understand how the political transition took place after Nehru;
- describe how the opposition unity and the Congress split posed a challenge to Congress dominance;
- explain how a new
   Congress led by Indira
   Gandhi overcame these
   challenges; and
- analyse how new policies and ideologies facilitated the restoration of the Congress system.

- > नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली;
- ▶िवपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी;
- ≽इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नयी कांग्रेस किस तरह इन चुनौतियों से उबरी; और
- कैसे नयी नीतियों तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की?

#### Challenge of Political Succession

Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away in May 1964. He had been unwell for more than a year. This had generated a lot of speculation about the usual question of succession: after Nehru, who? But in a newly independent country like India, this situation gave rise to a more serious question: after Nehru, what?

राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई। वे पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बडे अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन? लेकिन. भारत जैसे नव-स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या?

The second question arose from the serious doubts that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after Nehru. It was feared that like so many other newly independent countries, India too would not be able to manage a democratic succession. A failure to do so, it was feared, could lead to a political role for the army. Besides, there were doubts if the new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution.

भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यहां नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था। आशंका थी कि बाकी बहुत से नव-स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। इसके अतिरिक्त, इस बात को लेकर भी संदेह थे कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी हैं और नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नहीं।

The 1960s were labelled as the 'dangerous decade' when unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional divisions etc. could lead to a failure of the democratic project or even the disintegration of the country.

1960 के दशक को 'खतरनाक दशक' कहा जाता है क्योंकि गरीबी, गैर-बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता।

#### From Nehru to Shastri

The ease with which the succession after Nehru took place proved all the critics wrong. When Nehru passed away, K. Kamraj, the president of the Congress consulted party leaders party and Congress members of Parliament and found that there was a consensus in favour Lal Bahadur Shastri. He was unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus became the country's next Prime Minister. Shastri was a non-controversial leader from Uttar Pradesh who had been a Minister in Nehru's cabinet for many years. Nehru had come to depend a lot on him in his last year. He was known for his his commitment simplicity and principles. Earlier he had resigned from the position of Railway Minister accepting moral responsibility for a major railway accident.

#### नेहरू के बाद शास्त्री

नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे-से रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के. कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह-मशविरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लालबहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। शास्त्री. कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री, उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज्यादा-से-ज्यादा निर्भर होते गए थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए रेलमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे।

Shastri was the country's Prime Minister from 1964 to 1966. **During Shastri's brief Prime** Ministership, the country faced major challenges. While two India was still recovering from the economic implications of the war with China, failed monsoons, drought and serious food crisis presented a grave challenge. As discussed in the previous chapter, the country also faced a war with Pakistan in 1965. Shastri's famous slogan Jawan Jai Kisan', symbolised the country's resolve to face both these challenges.

शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत, चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सुखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर, 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। शास्त्री ने 'जय जवान-जय किसान' का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है।

**Shastri's Prime Ministership** came to an abrupt end on 10 January 1966, when he suddenly expired in Tashkent, then in USSR and currently the capital of Uzbekistan. He was there to discuss and sign an agreement with Muhammad Ayub Khan, the then President of Pakistan, to end the war.

प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहान्त हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे।

#### From Shastri to Indira Gandhi

Thus the Congress faced the challenge शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दुबारा of political succession for the second time in two years. This time there was Minister at the centre. Indira Gandhi, the daughter of Jawaharlal Nehru, had decided to back Indira Gandhi, but the decision was not unanimous. The ballot among Congress MPs.

#### शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी

राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ। intense competition between इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच Morarji Desai and Indira Gandhi. कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत Morarji Desai had earlier served as (मौजूदा महाराष्ट और गुजरात) के मुख्यमंत्री के Chief Minister of Bombay state (today's पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री Maharashtra and Gujarat) and also as a पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद been Congress President in the past पर रह चुकी थीं। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने and had also been Union Minister for सूचना मंत्रालय का प्रभार सँभाला था। इस दफा Information in the Shastri cabinet. This पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन time the senior leaders in the party देने का मन बनाया लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। एसे में प़ contest was resolved through a secret रैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया।

Indira Gandhi defeated
Morarji Desai by securing the
support of more than twothirds of the party's MPs. A
peaceful transition of power,
despite intense competition
for leadership, was seen as a
sign of maturity of India's
democracy.

उन्हें कांग्रेस पार्टी के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया।

It took some time before the new Prime Minister could settle down. While Indira Gandhi had been politically active for very long, she had served as a minister under Lal Bahadur Shastri only for a short period. The senior Congress may have supported leaders Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience would compel her to dependent on them for support and guidance. Within a year of becoming Prime Minister, Indira Gandhi had to lead the party in a Lok Sabha election.

नए प्रधानमंत्री को जमने में थोडा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यों तो बडे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थीं. लेकिन लालबहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बडे कम दिनों से मंत्री पद पर थीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतया यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा-निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगी। प्रधानमंत्री बनने के एक साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनावों में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी।

Around this time, the economic situation in the country had further deteriorated, adding to her problems. Faced with these difficulties, she set out to gain control over the party and to demonstrate her leadership skills.

इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। इससे इंदिरा की कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गईं। इन कठिनाइयों के मद्देनजर उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की।

#### Fourth General Elections, **1967**

The year 1967 is considered a landmark year in India's In Chapter Two you read about how the Congress party was the dominant political force throughout the country from 1952 onwards. This trend was to undergo significant changes with the 1967 elections.

चौथा आम चुनाव, 1967

भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण political and electoral history. पडा़व माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनावों में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया।

#### Context of the elections चुनावों का संदर्भ

In the years leading up to the चौथे आम चुनावों के आने तक देश में fourth general elections, the had died in quick succession, and the new Prime Minister, who was being seen as a political novice, had been in office for less than a year. You will recall from the discussion in Chapter Three and in the previous section of this chapter that the period was fraught with grave economic crisis resulting from successive failure of monsoons, widespread drought, decline in agricultural production

country witnessed major बड़े बदलाव हो चुके थे। दो प्रधानमंत्रियों changes. Two Prime Ministers का जल्दी-जल्दी देहावसान हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद सँभाले हुए अभी पूरे एक साल का अरसा भी नहीं गुजरा था। साथ ही. इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज़ से कम अनुभवी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट.

serious food shortage, depletion of foreign exchange reserves, drop in industrial production and exports, combined with a sharp rise in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development. One of the first decisions of the Indira Gandhi government was to devaluate the Indian rupee, under what was seen to be pressure from the US. Earlier one US dollar could be purchased for less than Rs. 5; after devaluation it cost more than Rs. 7.

गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा-भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ सैन्य खर्चे में भारी बढोतरी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य-मद में लगाना पडा। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के श्रु आती फ़ैसलों में एक था- रुपये का अवमूल्यन करना। माना गया कि रुपये का अवमूल्यन अमरीका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में 1 अमरीकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो अब बढकर 7 रुपये हो गई।

situation The economic triggered off price rise. People started protesting against the increase in prices of essential commodities, food scarcity, growing unemployment and the overall economic condition in the country. Bandhs and hartals were called frequently across the country. The government saw the protests as a law and order problem and not as of people's expressions problems. This further increased public bitterness and reinforced popular unrest.

आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अकसर 'बंद' और 'हड़ताल' की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण किया।

The communist and socialist parties launched struggles for greater equality. You will read in the next chapter about how a group of communists who separated from the Communist Party of India (Marxist) to form the **Communist Party of India** (Marxist-Leninist) led armed agrarian struggles and organised peasant agitations. This period also witnessed some of the worst Hindu-Muslim riots since Independence.

साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी - लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनायी और सशस्त्र कृषक-विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही, इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे।

#### **Non-Congressism**

This situation could not have remained isolated from party politics in the country. Opposition parties were in the forefront of organising public protests and pressurising the overnment. Parties opposed to the Congress realised that the division of their votes kept the Congress in power. Thus parties that were entirely different and disparate in their programmes and ideology got together to form anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustments of sharing seats in others

#### गैर-कांग्रेसवाद

यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग-थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बँट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक-दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया।

They felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. The socialist leader Ram Manohar Lohia gave this strategy the name of 'non-Congressism'. He also produced a theoretical argument in its defence: Congress rule undemocratic and opposed to the interests of ordinary poor people; therefore, the coming together of non-Congress parties was for reclaiming necessary democracy for the people.

#### गैर-कांग्रेसवाद

यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग-थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बँट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक-दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया।

They felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. The socialist leader Ram Manohar Lohia gave this strategy the name of 'non-Congressism'. He also produced a theoretical argument in defence: Congress rule was undemocratic and opposed to the interests of ordinary poor people; therefore, the coming together of non-Congress parties was reclaiming for necessary democracy for the people.

इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने इस रणनीति को 'गैर-कांग्रेसवाद' का नाम दिया। उन्होंने 'गैर-कांग्रेसवाद' के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाप ह है इसलिए गैर-कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है. ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके।

#### **Electoral verdict**

It was in this context of heightened popular discontent and the polarisation of political forces that the fourth general elections to the Lok Sabha and State Assemblies were held in February 1967. The Congress was facing the electorate for the first time without Nehru.

#### चुनाव का जनादेश

व्यापक जन-असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी।

The results jolted the Congress at both the national and state levels. Many contemporary political observers described the election **'political** results as a earthquake'.The Congress manage to get a majority in the Lok Sabha, but with its lowest tally of seats and share of votes since 1952. Half the ministers in Gandhi's cabinet were Indira defeated. The political stalwarts who lost in their constituencies included Kamaraj in Tamil Nadu, S.K. Patil in Maharashtra, Atulya Ghosh in West Bengal and K. B. Sahay in Bihar.

चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को 'राजनीतिक भूकंप' की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे-तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था. लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थीं। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट से एस.केपाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुँह की खानी पड़ी थी।

The dramatic nature of the political change would be more apparent to at the State level. The Congress lost majority in as many as seven States. In two other States defections prevented it from forming a government. These nine States where the Congress lost power were spread across the country - Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, Madras and Kerala. In Madras State (now called Tamil Nadu), a regional party — the **Dravida** Munnetra Kazhagam (DMK) – came to power by securing a clear majority.

राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नज़र आएगी। कांग्रेस को सात राज्यों में बहुमत नहीं मिला। दो अन्य राज्यों में दलबदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। ये राज्य पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत (अब इसे तिमलनाड़ कहा जाता है) में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड मुनेत्र कषगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड मुनेत्र कषगम (डीएमके) हिंदी-विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी।

The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the centre on the issue of imposition of Hindi as the official language. This was the first time any non-Congress party had secured a majority of its own in any State. In the other eight States, coalition governments consisting of non-Congress different parties were formed. A popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah and not through a single Congress ruled State. It was a strange feeling for those who were used to seeing the Congress in power. So, was the domination of the Congress over?

यहां के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर-कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य आठ राज्यों में विभिन्न गैर-कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो, तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस-शासित राज्य से होकर नहीं गुज़रेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया?

#### **Coalitions**

The elections of 1967 brought into picture the phenomenon of coalitions. Since no single party majority, various had got nonCongress parties came together to form joint legislative parties (called Samyukt Vidhayak Dal in Hindi) that supported non-Congress governments. That is why these governments came to described **SVD** be as governments. In most of these cases the coalition partners were ideologically incongruent.

#### गठबंधन

1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आयी। चूँकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर-कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में एसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक-दूसरे से भिन्न थे।

The SVD government Bihar, for instance, included the two socialist parties -SSP and the PSP - along with the CPI on the left and Jana Sangh on the right. In Punjab it was called the 'Popular United Front' and comprised the two rival Akali parties at that time - Sant group and the Master group - with both the communist parties - the CPI and the CPI(M), the SSP, the Republican Party and the Bharatiya Jana Sangh.

मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवादी पार्टियां-एसएसपी और पीएसपी -शामिल थीं। इनके साथ इस सरकार में वामपंथी-सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ-भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को 'पॉपुलर य्नाइटेड फ्रंट' की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धो अकाली दल-संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआई (एम), एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे।

#### **Defection**

Another important feature of the politics after the 1967 election was the role played by defections in the making and unmaking of governments in the States. Defection means an elected representative leaves the party on whose symbol he/she was elected and joins another party. After 1967 general election, the Congress breakaway legislators played an important role in installing non-Congress governments in three States - Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The constant realignments and shifting political loyalties in this period gave rise to the expression 'Aya Ram, Gaya Ram'.

#### दल-बदल

1967 के चुनावों की एक खास बात दल-बदल भी है। इसने राज्यों में सरकारों के बनने-बिगड्ने में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो इसे दल-बदल कहते हैं। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने तीन राज्यों हिरयाणा. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश—में गैर-कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभायी। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल-बदल से 'आया राम-गया राम' का जुमला मशहूर हुआ।

#### The story of 'Aya Ram, Gaya Ram'

The expression 'aya ram, gaya ram' became popular in the political vocabulary in India to describe the practice of frequent floor-crossing by legislators. Literally translated the terms meant, Ram came and Ram went. The expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gaya Lal, an MLA in Haryana, in 1967. He changed his party thrice in a fortnight, from Congress to United Front, back to Congress and then within nine hours to **United Front again** 

#### 'आया राम-गया राम'

विधायकों द्वारा तुरंत-फुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी-तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में 'आया राम-गया राम' का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के एक विधायक-गया लाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर तीन दफा अपनी पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस से युनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटों के अंदर दोबारा य्नाइटेड फ्रंट में चले गए।

It is said that when Gaya Lal declared his intention to quit the United Front and join the **Congress, the Congress** leader, Rao Birendra Singh brought him to Chandigarh press and declared "Gaya Ram was now Aya Ram". Gaya Lal's feat was immortalised in the phrase "Aya Ram, Gaya Ram" which became the subject of numerous jokes and cartoons. Later, the Constitution was amended to prevent defections

कहा जाता है कि जब गया लाल ने यनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेन्द्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ में प्रेस के सामने घोषणा की - ''गया राम था अब आया राम है।" गया लाल की इस हड़बड़ी को 'आया राम-गया राम' के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। उनकी इस हड्बड़ी को लेकर बहुत-से चुटकुले और कार्टून बने। बाद के समय में दल-बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया।

#### **Split in the Congress**

We saw that after the 1967 elections, the Congress retained power at the Centre but with a reduced majority and lost power in many States. More importantly, the results proved that the Congress could be defeated at the elections. But there was no substitute as yet. Most nonCongress coalition governments in the States did not survive for long. They lost majority, and either new combinations were formed or President's rule had to be imposed.

#### कांग्रेस में विभाजन

हमने देखा कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है। बहरहाल, अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर-कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाइं। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पडा़।

#### Indira vs. the 'Syndicate'

The real challenge to Indira Gandhi came not from the opposition but from within her own party. She had to deal with the 'syndicate', a group of powerful and influential leaders from within the Congress. The Syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by ensuring her election as the leader of the parliamentary party. These leaders expected Indira Gandhi to follow their advise. Gradually, however, **Indira** Gandhi attempted to her assert position within the government and the party. She chose her trusted group of advisers from outside the party. Slowly carefully, she sidelined and Syndicate.

#### इंदिरा बनाम सिंडिकेट

इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें 'सिंडिकेट' से निपटना पड़ा। 'सिंडिकेट' कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। 'सिंडिकेट' ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। बहरहाल, इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। धोरे-धोरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खडा किया।

her independence from the Syndicate. She also needed to work towards regaining the ground that the Congress had lost in the 1967 elections. Indira Gandhi adopted a very bold strategy. She converted a simple power struggle into an ideological struggle. She launched a series में बदल दिया। उन्होंने सरकार की initiatives to give government policy a Left orientation. She got the Congress Ten Point Programme in May दस-सूत्री कार्यक्रम अपनाया। 1967.

Indira Gandhi thus faced two इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का challenges. She needed to build सामना किया। उन्हें 'सिंडिकेट' के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की ज़रूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोयी थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। इंदिरा गाँधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनायी। उन्होंने एक साधारण से सत्ता-संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में Working Committee to adopt a कांग्रेस कार्यसमिति ने उनके प्रभाव से

This programme included social control of banks, nationalisation of General Insurance, ceiling on urban property and income, public distribution of food grains, land reforms and provision of house sites to the rural poor. While the 'syndicate' leaders formally approved this Leftwing programme, they had serious reservations about the same.

इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण. शहरी संपदा और आय के परिसीमन. खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। हालाँकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी. लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे।

#### The Congress 'Syndicate'

Syndicate was the informal name given to a group of Congress leaders who were in control of the party's organisation. It was led Kamraj, former Chief Minister of Tamil Nadu and then the president of the Congress party. It included powerful State leaders like S. K. Patil of Bombay city (later named as Mumbai), S. Nijalingappa of Mysore (later Karnataka), N. Sanjeeva Reddy of Andhra Pradesh and Atulya **Ghosh of West Bengal. Both Lal** Bahadur Shastri and later Indira Gandhi owed their position to the received from the support Syndicate.

#### कांग्रेस 'सिंडिकेट'

कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर 'सिंडिकेट' के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। 'सिंडिकेट' के अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के. कामराज थे। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बंबई सिटी (अब मुंबई) के एस.के. पाटिल, मैसूर (अब कर्नाटक) के एस. निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन. संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। लालबहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी. दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए थे

This group had a decisive say in Indira Gandhi's first Council of Ministers and also in policy formulation and implementation. After the **Congress split the leaders of** the syndicate and those owing allegiance to them stayed with the Congress (O). Since it was Indira Gandhi's **Congress (R) that won the test** of popularity, all these big and powerful men of Indian politics lost their power and prestige after 1971.

इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद् में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभायी थी। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडीकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस (ओ) में ही रहे। चूँकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आर) ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसलिए भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए।

#### Presidential election, 1969

The factional rivalry between the Syndicate and Indira Gandhi came in the open in 1969. Following President Zakir Hussain's death, the post of President of the India fell vacant that year. Despite Mrs Gandhi's reservations the 'syndicate' managed to nominate her long time opponent and then speaker of the Lok Sabha, N. Sanjeeva Reddy, as the official Congress candidate for the ensuing Presidential elections.

#### राष्ट्रपति पद का चुनाव, 1969

सिंडिकेट और इंदिरा गाँधी के बीच की गुटबाज़ी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गाँधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन. संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। एन. संजीव रेड्डी से इंदिरा गाँधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। एसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी।

Indira Gandhi retaliated by the then Viceencouraging President, V.V. Giri, to file his independent nomination as an candidate. She also announced several big and popular policy measures like the nationalisation of fourteen leading private banks and the abolition of the 'privy purse' or the special privileges given to former princes. Morarji Desai was the Deputy Prime Minister and Finance Minister. On both the above issues serious differences emerged between him and the Prime Minister resulting in Desai leaving the government.

उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि को बढावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। इंदिरा गांधी ने चौदह अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी 'प्रिवी पर्स' को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उपप्रधानमंत्री और वित्तमंत्री थे। उपर्युक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणामस्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया।

**Congress had seen** differences of this kind in the past. But this time both the parties wanted a showdown which took place during the Presidential elections. The then Congress President S. Nijalingappa issued a 'whip' asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favour of Sanjeeva Reddy, the official candidate of the party. **Supporters of Indira Gandhi** requisitioned a special meeting of the AICC (that is why this faction came to be known as 'requisitionists') but this was refused.

गुज़रे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने 'व्हिप' जारी किया कि सभी 'कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें।' इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की. लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई।

After silently supporting V.V. Giri, the Prime Minister openly called for a 'conscience vote' which meant that the MPs and MLAs from the Congress should be free to vote the way they want. The election ultimately resulted in the victory of V.V. Giri, the independent candidate, and the defeat of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate.

वी.वी. गिरि का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्ज़ी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वी.वी. गिरि ही विजयी हुए। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबिक एन. संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे।

The defeat of the official Congress candidate formalised the split in the **Congress** President The party. expelled the Prime Minister from the party; she claimed that her group was the real Congress. By November 1969, the Congress group led by the 'syndicate' came to be referred to as the Congress (Organisation) and the group led by Indira Gandhi came to be called the Congress (Requisitionists). parties two were **These** also described as Old Congress and New Congress. Indira Gandhi projected the split as an ideological divide between socialists and conservatives, between the pro-poor and the pro-rich.

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस (ऑर्गनाइजेशन) और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस (रिक्विजिनिस्ट) कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों को क्रमश: 'पुरानी कांग्रेस' और 'नयी कांग्रेस' भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे 'समाजवादी' और 'पुरातनपंथी' तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफ़दार के बीच की लड़ाई करार दिया।

#### **Abolition of Privy Purse**

In Chapter One you have read about the integration of the Princely **States.** This integration was preceded by an assurance that after the dissolution of princely rule, the rulers' families would allowed to retain certain private property, and given a grant in heredity or government allowance, measured on the basis of the extent, revenue and potential of merging state. This grant was called the privy purse. At the time of accession, there was little criticism of these privileges since integration and consolidation was the primary aim.

#### 'प्रिवी पर्स' की समाप्ति

पहले अध्याय में आपने देसी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था। देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरप ह से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएँगे। ये दोनों चीज़ें (यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते) इस बात को आधार मानकर तय की जाएँगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को 'प्रिवी पर्स' कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा-महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता, अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था।

Yet, hereditary privileges were not consonant with the principles of equality and social and economic justice laid down in the Constitution of India. Nehru had expressed his dissatisfaction over the matter time and again. Following the 1967 elections, Indira Gandhi supported the demand that the government should abolish privy purses. Morarji Desai, however, called the move morally wrong and amounting to a 'breach of faith with the princes'.

बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने 'प्रिवी पर्स' को खत्म करने की माँग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को 'प्रिवी पर्स' की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह 'रियासतों के साथ विश्वासघात' के बराबर होगा।

The government tried to bring a Constitutional amendment in 1970, but it was not passed in Rajya Sabha. It then issued an ordinance which was struck down by the Supreme **Court. Indira Gandhi made** this into a major election issue in 1971 and got a lot of public support. Following its massive victory in the 1971 election, the Constitution was amended to remove legal obstacles for abolition of 'privy purse'.

प्रिवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनी अड्चनें खत्म हो गई।

#### The 1971 Election and restoration of Congress

The split in the Congress reduced Indira Gandhi Government to a minority. Yet her government continued in office with the issuebased support of a few other parties including the Communist Party of India and the DMK. During this period the government made conscious attempts to project its socialist credentials. This was also phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land ceiling legislation.

#### 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन

कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल, डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ज़बरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने भू-परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए।

In order to end her dependence on other political parties, strengthen her party's position in the Parliament, and seek a popular mandate for her programmes, Indira Gandhi's government recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1970. This was another surprising and bold move. The fifth general election to Lok Sabha were held in February 1971.

दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मज़बूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफ़ारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए पाँचवें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए।

#### The contest

The electoral contest appeared to be loaded against Congress(R). After all, the new Congress was just one faction of an already weak party. **Everyone believed that the real** organisational strength the **Congress party was under** the command of Congress(O). To make matters worse for Indira Gandhi, all non-communist, the major nonCongress opposition parties formed an electoral alliance known as the Grand Alliance. The SSP, PSP, Bharatiya Jana Sangh, Swatantra Party and the Bharatiya Kranti Dal came together under this umbrella. The ruling party had an alliance with the CPI.

#### मुकाबला

चुनावी मुकाबला कांग्रेस (आर) के विपरीत जान पड रहा था। आखिर नयी कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस (ओ) के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त, सभी बड़ी गैर-साम्यवादी और गैर-कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे 'ग्रैंड अलायंस' कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांतिदल, चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड किया।

Yet the new Congress had something that its big opponents lacked - it had an issue, an agenda and a positive slogan. The Grand Alliance did not have a coherent political programme. Indira Gandhi said that the opposition alliance had only one common programme: Indira Hatao (Remove Indira). In contrast to this, she put forward a positive programme captured in the famous Garibi Hatao slogan: (Remove Poverty). She focused on the growth of the public sector, imposition of ceiling on rural land holdings and urban property, removal of disparities in income and opportunity, and abolition of princely privileges.

इसके बावजूद नयी कांग्रेस के साथ एक एसी बात थी, जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नयी कांग्रेस के पास एक मुद्दा था; एक अजेंडा और कार्यक्रम था। 'ग्रैंड अलायंस' के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम-घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है: इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे 'गरीबी हटाओ' के ज़रिए एक शक्ल प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की संवृद्धि, ग्रामीण भू-स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा 'प्रिवी पर्स' की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में ज़ोर दिया।

Through garibi hatao Indira Gandhi tried to generate a support base among the disadvantaged, especially among the landless labourers, **Dalits and Adivasis,** minorities, women and the unemployed youth. The slogan of garibi hatao and the programmes that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support base.

'गरीबी हटाओं' के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। 'गरीबी हटाओ' का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थीं।

#### The outcome and after

The results of the Lok Sabha elections of 1971, were as dramatic as was the decision to hold these elections. The Congress(R)-CPI alliance won more seats and votes than the Congress had ever won in the first four general elections. The combine won 375 seats in Lok Sabha and secured 48.4 per cent votes. Indira Gandhi's Congress(R) won 352 seats with about 44 per cent of the popular votes on its own.

#### परिणाम और उसके बाद...

1971 के लोकसभा चुनावों के नतीजे उतने ही नाटकीय थे, जितना इन चुनावों को करवाने का पृ रेसला। कांग्रेस (आर) और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिलीं. उतनी कांग्रेस पिछले चार आम चुनावों में कभी हासिल न कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिलीं और इसने कुल 48.4 प्रतिशत वोट हासिल किए। अकेले इंदिरा गाँधी की कांग्रेस (आर) ने 352 सीटें और 44 प्रतिशत वोट हासिल किए थे।

**Contrast this with the** performance of the Congress(O): the party with so many stalwarts could get less than one-fourth of the votes secured by Indira Gandhi's party and win merely 16 seats. With this the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the 'real' Congress and restored to it the dominant position in Indian politics. The **Grand Alliance of the** opposition proved a grand failure. Their combined tally of seats was less than 40.

अब जरा इस तसवीर की तुलना कांग्रेस (ओ) के उजाड से करें: इस पार्टी में बडे-बडे महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे. उसके एक-चौथाई वोट ही इसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज़ 16 सीटें मिलीं। अपनी भारी-भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही 'असली कांग्रेस' है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी 'ग्रैंड अलायंस' धराशायी हो गया था। इस 'महाजोट' को 40 से भी कम सीटें मिली थीं।

Soon after the 1971 Lok Sabha elections, a major political and military crisis broke out in East Pakistan (now Bangladesh). As you have read in Chapter Four, the 1971 elections were followed by the crisis in East Pakistan and the IndoPak war leading to the establishment of Bangladesh. These events added to the popularity of Indira Gandhi. Even the opposition leaders admired her statesmanship. Her party swept through all the State Assembly elections held in 1972. She was seen not only as the protector of the poor and the underprivileged, but also a strong nationalist leader. The opposition to her, either within the party or outside of it, simply did not matter.

1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खडा हुआ। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत-पाक के बीच युद्ध छिड गया। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चाँद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज्यकौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मज़बूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश न बची।

With two successive election victories, one at the centre and other at the State level, the dominance of the Congress was restored. The Congress was now in power in almost all the States. It was also popular across different social sections. Within a span of four years, Indira Gandhi had warded off the challenge to her leadership and to the dominant position of the Congress party.

कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में जीती थी और राज्य स्तर के चुनावों में भी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज चार साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को ध्ल चटा दी थी।

#### **Restoration?**

But does it mean that the **Congress system was** restored? What Indira Gandhi had done was not a revival of the old Congress party. In many ways she had reinvented the party. The party occupied a similar position in terms of its popularity as in the past. But it was a different kind of a party. It relied entirely on the popularity of the supreme leader. It had a somewhat weak organisational structure.

#### कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन?

बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया, वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नयी तर्ज़ पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था, जो उसे श्रु आती दौर में हासिल था. लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतया अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक

This Congress party now did not have many factions, thus it could not accommodate all kinds of opinions and interests. While it won elections, it depended more on some social groups: the poor, the women, Dalits, Adivasis and the minorities. This was a new Congress that had emerged. Thus Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself.

इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वगों जैसे गरीब. महिला. दलित. आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभरकर सामने आई, वह एकदम नयी कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित ज़रूर किया, लेकिन कांग्रेस-प्रणाली की प्रकृति को बदलकर।

Despite being more popular, the new Congress did not have the kind of capacity to absorb all tensions and conflicts that the Congress system was known for. While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people's aspirations actually shrank.

कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था. लेकिन नयी कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड मज़बूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई।

The popular unrest and mobilisation around issues of development and economic deprivation continued to grow. In the next chapter you will read about how this led to a political crisis that threatened the very existence of constitutional democracy in the country.

विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। अगले अध्याय में आप पढ़ंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मॅंडराने लगा था।